## खबर संक्षेप

### मांगे पूरी न होने पर रामपुर बटुरा खदान ठप करने की खुली चेतावनी!

**शहडोल।** जिले के बुढ़ार जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत अतरिया में एसईसीएल प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा है। रामपुर बटुरा ओपन कास्ट कोयला खदान विस्तार परियोजना के नाम पर आदिवासियों और किसानों की जमीनें हड़पने पर आमादा प्रबंधन को अब स्थानीय जनता ने सीधी चुनौती दे दी है। ग्राम पंचायत अतरिया ने प्रभावित किसानों के हितों की रक्षा और स्थानीय युवाओं को रोजगार की गारंटी के बिना इस विस्तार परियोजना को किसी भी कीमत पर स्वीकार करने से साफ़ इनकार कर दिया है।
कलेक्टर शहडोल को सौंपे गए कड़े शिकायती पत्र में ग्राम पंचायत अतरिया और किसान एकता संघ ने एसईसीएल प्रबंधन की कारगुजारियों को सरेआम बेनकाब किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि 18 जुलाई 2025 को आयोजित डी.आर.आर.सी. की बैठक में एसईसीएल प्रबंधन द्वारा स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक उसे मंजूरी नहीं दी गई। हद तो यह है कि परियोजना क्षेत्र में सक्रिय ढोलू कांट्रैक्शन और जय अम्बे जैसी बाहरी ठेका कंपनियां अतरिया के संपूर्ण रूप से प्रभावित क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को दरकिनार कर बाहरी लोगों को पाल रही हैं।
आक्रोशित ग्रामीणों ने दो टूक मांग की है कि जब तक प्रभावित पात्र किसानों और उनके परिवारों को भूमि के बदले रोजगार नहीं मिलता, तब तक खदान विस्तार के समस्त कार्य और कागजी कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाई जाए।
एक तरफ जहां खदानों से अरबों का कोयला निकाला जा रहा है, वहीं अतरिया पंचायत आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है। ज्ञापन में मांग की गई है कि जर्जर हाल में जी रहे ग्राम पंचायत अतरिया में तत्काल नए पंचायत भवन समेत कक्षा 1 से 8 तक के लिए प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के नवीन भवनों की स्वीकृति दी जाए। इसके साथ ही प्रभावित ग्रामीणों के उचित पुनर्वास, पर्यावरण व आजीविका संरक्षण, स्वास्थ्य और शुद्ध पेयजल जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई है। ग्रामीणों का साफ़ कहना है कि 6 मिलियन टन वार्षिक कार्य चालू करने से पहले पूरे अतरिया गांव को स्पष्ट तौर पर नोटिफाई किया जाए।
मामले में ग्राम पंचायत अतरिया के सरपंच और किसान एकता संघ के प्रदेश प्रभारी अमित शर्मा के तेवर बेहद आक्रामक हैं। उन्होंने महाप्रबंधक को खुली चेतावनी दी है कि यदि 10 जुलाई 2026 से 17 जुलाई 2026 के बीच इन न्यायोचित मांगों का ठोस निराकरण नहीं किया गया, तो 18 जुलाई 2026 से पूरा अतरिया गांव दुर्गा मंदिर के सामने क्रमिक भूख हड़ताल और उग्र धरना-प्रदर्शन पर बैठ जाएगा। विवश होने पर ग्रामीण रामपुर बटुरा प्रोजेक्ट का पूरा काम बंद करा देंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन, प्रशासन और एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र प्रबंधक की होगी।

# शिकायती माफिया विकास सचदेव का किला ध्वस्त

## ब्लैकमेलर की कुंडली खंगालकर पुलिस ने कसा शिकंजा, गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज

**उमरिया।** पवित्र लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनहित के कानूनों को ब्लैकमेलिंग का हथियार बनाने वाले एक बेहद शातिर शिकायती माफिया का मुखौटा आखिरकार कानून ने बेरहमी से नोच फेंका है। जिला मुख्यालय सहित समूचे मध्य प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में अपनी झूठी और प्रायोजित शिकायतों से आतंक का कुत्सित साम्राज्य चलाने वाले कुख्यात मास्टरमाइंड विकास सचदेव के खिलाफ उमरिया पुलिस ने गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज कर ली है। इस सफेदपोश आरोपी के पापों का घड़ा तब फूटा, जब शहर के प्रतिष्ठित एवं सजग व्यवसायी विनोद आहूजा ने इसकी अवैध उगाही और मानसिक प्रताडऩा के आगे घुटने टेकने के बजाय कानून की ताकत पर भरोसा जताया। विनोद आहूजा की साहसिक विधिक पहल और ठोस सबूतों के आधार पर पुलिस ने इस शातिर ब्लैकमेलर की पूरी कुंडली खंगालकर उसे कानून के शिकंजे में कस दिया है। इस बड़ी दंडात्मक कार्रवाई के बाद अंचल के व्यापारियों, समाजसेवियों और रात-दिन जनता की सेवा में जुटे ईमानदार शासकीय अधिकारियों ने चैन की सांस ली है।

### सीएम हेल्पलाइन उगाही का अड्डा

पुलिस की शुरुआती तफ्तीश और दर्ज

एफआईआर के पन्नों से जो सनसनीखेज सच बाहर आया है, उसने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है। लोक-कल्याणकारी योजनाओं और पारदर्शी व्यवस्था के लिए बनाए गए तंत्र का आरोपी विकास सचदेव ने अपने व्यक्तिगत आर्थिक स्वार्थों के लिए बेरहमी से सौदा किया। आरोपी ने मुख्यमंत्री कार्यालय, कलेक्ट्रेट जनसुनवाई, लोकायुक्त, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ और भोपाल के मंत्रालय स्तर तक कोई भी ऐसा जिम्मेदार दफ्तर खाली नहीं छोड़ा था, जहां उसने अपनी ईर्ष्या, द्वेष और कुंठा को शांत करने के लिए मनगढ़ंत शिकायतों के पुलिंदे न भेजे हों। विभागीय रिकॉर्ड गवाही दे रहे हैं कि उमरिया जिले के इतिहास में सबसे ज्यादा झूठे, भ्रामक और तथ्यहीन आवेदन देने का काला और शर्मनाक रिकॉर्ड इसी शातिर अपराधी के नाम दर्ज है।

### इज्जत नीलाम करने की धमकी और बंद कमरों में सौदा

जांच में इस माफिया के काम करने के एक फिक्स और क्रूर पैटर्न का खुलासा हुआ है। आरोपी विकास सचदेव का धंधा बेहद व्यवस्थित था। वह पहले क्षेत्र के किसी प्रतिष्ठित नागरिक, सफल व्यापारी या सीधे-साधे अधिकारी को चिन्हित करता था। इसके बाद वह तकनीकी और कानूनी शब्दों का मायाजाल बुनकर एक बेबुनियाद और फर्जी शिकायत तैयार करता था। शिकायत दर्ज कराने के बाद वह पीड़ित को समाज में उसकी इज्जत नीलाम करने और अदालती पचड़ों में फंसाने का डर दिखाता था। अंत में, बदनामी से डर रहे पीड़ित को बंद कमरों में बुलाकर लाखों रुपये की अवैध उगाही की जाती थी। जो भी स्वाभिमानी व्यक्ति इसकी इन नाजायज और अनैतिक मांगों के आगे नहीं झुका, उसके खिलाफ आरोपी शिकायतों की झड़ी लगा देता था। सच तो यह है कि ब्लैकमेलिंग और उगाही ही इस कथित सदाचारी की रोजी-रोटी का मुख्य जरिया बन चुकी थी।

### दीमक की तरह चाटा प्रशासनिक तंत्र

इस छद्मवेशी अपराधी ने पूरी शासकीय मशीनरी का मखौल उड़ा कर रख दिया था। हर दिन नए-नए नाम बदलकर, बेनामी स्रोतों का हवाला देकर या खुद के नाम से झूठी अर्जियां लगाना इसका पूर्णकालिक धंधा था। इसका मुख्य मकसद प्रशासनिक अधिकारियों को हमेशा दबाव और दहशत में रखना था, ताकि वे इसके किसी भी गलत काम का विरोध न कर सकें। इस शिकायती आतंक का सबसे घातक असर आम जनता पर पड़ रहा था। जिले के दफ्तरों में वास्तविक जरूरतमंदों और गरीबों की फाइलें धूल खाती रहीं, क्योंकि विभागों के जिम्मेदार अधिकारी दिन-रात सिर्फ इस माफिया की फर्जी और उलझाऊ शिकायतों का जवाब तैयार करने में व्यस्त रहते थे।

### अब खंगाला जा रहा है पूरा काला चि_ा

व्यवसायी विनोद आहूजा की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के बाद पुलिस कप्तान के निर्देश पर इस आदतन अपराधी के पिछले सभी काले कारनामों के रिकॉर्ड जब्त करने शुरू कर दिए गए हैं। उमरिया जिले का कोई भी कोना—चाहे वह राजस्व विभाग हो, वन विभाग हो, खनिज विभाग हो, आबकारी हो या खुद पुलिस महकमा हो—इसके फर्जी शिकायतों के मकडज़ाल से अछूता नहीं था। अकेले जनसुनवाई में इसके द्वारा दिए गए आवेदनों की संख्या सैकड़ों में है।

### पुलिसिया कार्रवाई और तकनीकी साक्ष्य

मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जांच में फॉरेंसिक और तकनीकी साक्ष्यों को भी शामिल किया है। आरोपी के मोबाइल कॉल डिटेल्स, व्हाट्सएप चैट्स और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की गहनता से कडिय़ों को जोड़ा जा रहा है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस मामले में विकास सचदेव के साथ पर्दे के पीछे से जुड़े कुछ अन्य सफेदपोशों और मददगारों के नाम भी सामने आ सकते हैं। कानून के इस कड़े प्रहार ने यह साफ संदेश दे दिया है कि आरटीआई और जनसुनवाई जैसे जनहितैषी माध्यमों को ब्लैकमेलिंग की ढाल बनाने वाले अपराधियों की सही जगह समाज नहीं, बल्कि जेल की सलाखें हैं। पुलिस आरोपी की धरपकड़ और आगे की दंडात्मक कानूनी प्रक्रियाओं में जुट गई है।

# ओवर लोडिंग और उड़ती राख से जनता बेहाल

**कमिश्नर दफ्तर पहुंची जैतहरी की गूंज, मोजर बेयर पावर प्लांट और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की साठगांठ से सुलग रहा इलाका**

### नो-एंट्री लगाने और सडक़ों को बर्बाद करने वाली कंपनी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग

**शहडोल।** संभाग अनूपपुर जिले के जैतहरी में स्थापित मोजर बेयर (एमबी) पावर प्लांट लिमिटेड से निकलने वाली कालिख और उड़ती राख (फ्लाई ऐश) ने अब पूरे संभाग के प्रशासनिक गलियारे में हडक़ंप मचा दिया है। नगर परिषद जैतहरी के वार्ड क्रमांक 06 की मुखर पार्षद श्रीमती हेमलता मोटवानी ने सीधे कमिश्नर के समक्ष इस पूरे काले कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए एक तीखा शिकायती पत्र सौंपा है। इस शिकायत ने न केवल मोजर बेयर पावर प्लांट प्रबंधन के दावों की हवा निकाल दी है, बल्कि क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शहडोल की संदेहास्पद चुप्पी और कार्यप्रणाली को भी सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोप है कि प्रदूषण विभाग के आला अधिकारी दफ्तरों में बैठकर सब ठीक है का चश्मा पहने हुए हैं, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि उड़ती राख से जनता का दम घुट रहा है।

### नियमों को ठेंगा दिखा रही एच.आर.सी. कंपनी

शिकायत में सीधे तौर पर मोजर बेयर प्लांट में फ्लाई ऐश परिवहन का ठेका लेने वाली एच.आर.सी. कंपनी पर गंभीर आरोप मढ़े गए हैं। कंपनी द्वारा परिवहन नियमों और आरटीओ के गाइडलाइंस को ताक पर रखकर भारी वाहनों में बेतरतीब ओवरलोडिंग की जा रही है। इस अनियंत्रित ओवरलोडिंग का नतीजा यह है कि करोड़ों की लागत से बनी अनूपपुर से वेंकटनगर मुख्य मार्ग का नामोनिशान मिटने लगा है। सडक़ कई जगहों पर पूरी तरह धंस चुकी है और बीचों-बीच ऐसी लंबी और गहरी दरारें पड़ गई हैं, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे को न्योता दे रही हैं। स्थानीय लोग इसे विकास के नाम पर विनाश का मार्ग कहने लगे हैं।

### तिरपाल के नाम पर केवल खानापूर्ति, जनता के फेफड़ों में घुल रहा जहर

मोजर बेयर पावर प्लांट और पर्यावरण विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही यह है कि फ्लाई ऐश जैसे संवेदनशील और जानलेवा कचरे को खुले आम सडक़ों पर दौड़ाया जा रहा है। वाहनों को सुरक्षित तरीके से पैक करने के बजाय महज कामचलाऊ तिरपाल फेंककर औपचारिकता पूरी की जा रही है। तेज हवाओं के चलते यह राख उडक़र सीधे पीछे चल रहे दोपहिया वाहन चालकों की आंखों में गिरती है, जिससे लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। सबसे घातक बात यह है कि यह सूक्ष्म राख हवा में घुलकर स्थानीय बुजुर्गों, बच्चों और आम जनता के फेफड़ों में समा रही है, जिससे सांस और दमा जैसी गंभीर बीमारियां महामारी का रूप ले रही हैं। लेकिन, शहडोल का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस जनहानि को देखकर भी पूरी तरह मौन साधे बैठा है, जिससे उसकी साठगांठ के कयासों को बल मिल रहा है।

### स्थानीय बेरोजगारों से अवैध वसूली का खेल

पार्षद ने कमिश्नर को बताया कि जैतहरी नगर के मुख्य मार्गों और राठौर चौक पर सुबह 08 से 11 बजे और दोपहर 2:30 से 4:30 बजे के बीच स्कूल और कॉलेज के छात्र-छात्राओं की भारी आवाजाही होती है। ठीक इसी व्यस्ततम समय में मोजर बेयर के ये यमदूत (भारी राखड़ वाहन) सडक़ों पर अंधाधुंध दौड़ते हैं, जिससे मासूमों की जान हमेशा जोखिम में बनी रहती है। इसके अलावा, मोजर बेयर प्लांट और परिवहन कंपनी का एक और काला चेहरा सामने आया है। स्थानीय स्तर पर पावर प्लांट होने के बावजूद जैतहरी के स्थानीय वाहन मालिकों को रोजगार से वंचित कर दिया गया है। दूर-दराज के क्षेत्रों से गाडिय़ां बुलाई जा रही हैं और यदि कोई स्थानीय व्यक्ति रोजगार की मांग करता है, तो उससे गाड़ी लगाने के नाम पर मोटी रकम (अवैध वसूली) की मांग की जाती है। इस पक्षपात और तानाशाही रवैये से स्थानीय बेरोजगारों और वाहन मालिकों में भारी आक्रोश व गहरा रोष व्याप्त है।

### लगे नो-एंट्री और हो निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच

श्रीमती हेमलता मोटवानी ने शहडोल कमिश्नर से स्पष्ट शब्दों में मांग की है कि अनूपपुर और बिजुरी नगरीय निकायों की तर्ज पर जैतहरी नगर के भीतर भी दिन के समय इन भारी फ्लाई ऐश वाहनों पर तत्काल प्रभाव से नो-एंट्री लागू की जाए। नियमों के विपरीत खुले में ओवरलोड परिवहन करने वाली एच.आर.सी. कंपनी और पर्यावरण मानकों की अनदेखी करने वाले मोजर बेयर प्लांट पर तत्काल रोक लगाई जाए। सडक़ों को हुए भारी नुकसान का आकलन कर इसकी पूरी आर्थिक भरपाई एच.आर.सी. कंपनी और प्लांट प्रबंधन से वसूली जाए। इस पूरे खेल में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शहडोल की भूमिका की भी उच्चस्तरीय जांच हो।

# जिला पंचायत के मुखिया के विरोध में लामबंद हुए सरपंच मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

**शहडोल।** जिला पंचायत शहडोल में इन दिनों लोकतंत्र और प्रशासनिक मर्यादा को ताक पर रखकर साहब का डंडा चल रहा है। जनता द्वारा चुनी गई एक आदिवासी महिला जनप्रतिनिधि को दफ्तर बुलाकर सरेआम जलील करने और उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का एक बेहद संगीन मामला सामने आया है। मामला जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिवम प्रजापति से जुड़ा है। उन पर ग्राम पंचायत बोडरी की महिला सरपंच श्रीमती गनेसिया बाई ने गंभीर और अमर्यादित व्यवहार के सनसनीखेज आरोप मढ़े हैं। इस अफ़सरशाही के अहंकार के खिलाफ शुक्रवार को जिले भर के सरपंचों का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा।

शुक्रवार को आक्रोशित सरपंचों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर आरोपी सीईओ के खिलाफ तत्काल कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की। इस दौरान कलेक्ट्रेट प्रांगण सरपंचों के तीखे नारों से दहल उठा। सरपंचों ने खुलेआम मोर्चा खोलते हुए सीईओ तेरी तानाशाही नहीं चलेगी और जिला पंचायत सीईओ मुर्दाबाद के गगनभेदी नारे लगाए। जनप्रतिनिधियों का साफ कहना है कि जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

शिकायती पत्र के मुताबिक, यह शर्मनाक वाकया बीती 6 जुलाई 2026 का है। पीड़ित सरपंच गनेसिया बाई का आरोप है कि जब वह जिला पंचायत कार्यालय पहुंचीं, तो सीईओ शिवम प्रजापति ने उनके साथ न सिर्फ अभद्र व्यवहार किया, बल्कि शासकीय सेवा आचरण नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा दीं। सरपंच ने मांग की है कि घटना के दिन दोपहर 12 बजे के बाद की जिला पंचायत कार्यालय की सीसीटीवी फुटेज को तुरंत सुरक्षित और सार्वजनिक किया जाए।

उन्हें आशंका है कि अफ़सर अपने रसूख का इस्तेमाल कर इस पुख्ता डिजिटल सबूत को मिटाने या साक्ष्यों को नष्ट करने की साजिश रच सकते हैं। घटना के वक्त सरपंच के पति और गांव का एक अन्य नागरिक भी इस तानाशाही का चश्मदीद गवाह है।

इस बदसलूकी से आहत आदिवासी महिला सरपंच ने अफ़सरशाही के इस घमंड के खिलाफ सीधे भोपाल में बैठे प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, संभागायुक्त और मध्य प्रदेश महिला आयोग को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है, जिससे पूरे प्रशासनिक अमले में हडक़ंप मच गया है। महिला जनप्रतिनिधि के तेवर बेहद आक्रामक हैं। उन्होंने साफ लफ्जों में चेतावनी दी है कि यदि इस गंभीर मामले में तय समय सीमा के भीतर निष्पक्ष जांच और आरोपी अधिकारी पर गाज नहीं गिरी, तो वह मामले को दबाने की हर कोशिश को नाकाम करते हुए सीधे जबलपुर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करेंगी।

# विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

**शहडोल।** उमंग स्वास्थ्य केंद्र द्वारा संचालित राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं के लिए एक स्वास्थ्य जागरूकता एवं परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय के समाज कार्य एवं समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नीलिमा खरे जी के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम में जिला चिकित्सालय शहडोल से किशोर स्वास्थ्य परामर्शदाता पूनम सिंह ने आउटरीच गतिविधि के माध्यम से छात्र-छात्राओं को किशोर स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की।

परामर्शदाता ने संतुलित आहार एवं पोषण, एनीमिया के कारण एवं बचाव, व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, किशोरावस्था में वृद्धि एवं विकास, यौवनारंभ के दौरान होने वाले शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन, विवाह की वैधानिक आयु, गर्भनिरोधक उपाय, मासिक धर्म एवं मासिक धर्म स्वच्छता, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, यौन संचारित संक्रमण, एचआईवी/एड्स तथा मानसिक तनाव एवं तनाव प्रबंधन जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हुए विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। कार्यक्रम का समन्वय मास्टर ऑफ सोशल वर्क (एम एस डब्ल्यू) के विजिटिंग फैकल्टी नितिन गर्ग द्वारा किया गया। इस अवसर पर समाजशास्त्र विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. जितेंद्र सेन,सिद्धार्थ मिश्रा, राकेश मिश्रा, कल्याणी उपाध्याय सहित अन्य शिक्षकों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में एम एस डब्ल्यू के छात्र-छात्राओं में रामबाबू पटेल, खुशबू मिश्रा, कीर्ति पाव, धनेश्वरी, श्वेता तिवारी, मुस्कान शुक्ला एवं कुसुम प्रजापति ने चर्चा में अपने विषयों को रखा उस दौरान अनेक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा किशोर स्वास्थ्य संबंधी विषयों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया।

# विचारपुर आवासीय विद्यालय के 17 बच्चे एक साथ बीमार

**शहडोल।** सरकारी दावों और भारी-भरकम बजट के बावजूद नौनिहालों की सुरक्षा को लेकर हॉस्टल प्रबंधन कितना लापरवाह है, इसकी जीती-जागती मिसाल शुक्रवार को विचारपुर आवासीय ज्ञानोदय विद्यालय में देखने को मिली। यहां अव्यवस्थाओं और कथित सीजनल बीमारी के चलते एक साथ 17 मासूम बच्चे बीमार हो गए। हॉस्टल में बच्चों के तड़पने के बाद भी जब जिम्मेदार अफ़सर और वार्डन गहरी नींद से नहीं जागे, तो वहां के मुस्तैद चौकीदार ने मोर्चा संभाला। घटना के बाद कैंपस में हडक़ंप मच गया और अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया। हॉस्टल प्रबंधन की इस घोर लापरवाही के बीच विद्यालय के चौकीदार अजय प्रजापति ने देवदूत बनकर कमान संभाली और आनन-फानन में सभी बच्चों को अकेले ही जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका आपातकालीन इलाज जारी है। इस घटना ने आवासीय विद्यालय की मॉनिटरिंग और बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति बरती जा रही घोर लापरवाही की कलई खोलकर रख दी है। स्थानीय लोगों में आक्रोश है कि जब इतने बड़े पैमाने पर बच्चे बीमार थे, तो हॉस्टल का प्रशासनिक अमला कहां गायब था, क्या अफ़सर किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं?

# धधकते गैस सिलेंडर और खुले कुएं के साए में दांव पर देश का भविष्य!

**शहडोल।** सरकारें हर साल करोड़ों का बजट फूंककर स्कूल चलें हम के विज्ञापनों से अखबारों के पन्ने रंगती हैं। अफ़सर कागजों पर चमचमाती व्यवस्थाओं की झूठी तस्वीरें पेश करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इस खोखले सिस्टम के मुंह पर करारा तमाचा मार रही है। आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले के बुढ़ार विकासखंड से एक ऐसी खौफनाक और शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर किसी भी संवेदनशील इंसान की रूह कांप जाए। यहां शासकीय माध्यमिक विद्यालय अतरिया में कक्षा 1 से 8 तक के मासूम बच्चे किसी सुरक्षित स्कूल भवन में नहीं, बल्कि मौत के साए के बीच ककहरा सीखने को मजबूर हैं।

कहने को तो अतरिया में विद्यालय भवन है, लेकिन अफ़सरशाही की लापरवाही के कारण वह इस कदर जर्जर हो चुका है कि कभी भी भरभराकर गिर सकता है। नतीजतन, बच्चों को सामुदायिक भवन और खुले सांस्कृतिक रंगमंच पर बिठाया जा रहा है। सबसे डरावना सच यह है कि जिस बंद कमरे के भीतर ठूस-ठूस कर मासूमों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक उसी कमरे में मिड-डे मील (मध्यान्ह भोजन) का खाना बनाने के लिए धधकती आग के साथ गैस सिलेंडर रखा गया है। जरा सोचिए, एक छोटी सी तकनीकी चूक या रिसाव पल भर में दर्जनों मासूमों को मौत की नींद सुला सकता है। क्या शिक्षा विभाग यहां किसी बड़े अग्निकांड का इंतजार कर रहा है।

जो बच्चे इस छोटे से कमरे में नहीं समा पाते, उन्हें बाहर सांस्कृतिक मंच पर खुले आसमान के नीचे भगवान भरोसे बिठा दिया जाता है। सितम देखिए कि इस खुले मंच के ठीक बगल में एक गहरा और खुला हुआ कुआं यमदूत बनकर मुंह बाए खड़ा है। बरसात के इस मौसम में चारों तरफ फिसलन और जलभराव है। खेलते-कूदते अगर किसी मासूम का पैर जरा सा भी फिसला, तो उसका सीधा कुएं में गिरना तय है। नौनिहाल हर दिन किताबों के साथ अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं और जनप्रतिनिधियों से लेकर अफ़सरों तक से स्कूल भवन की भीख मांग रहे हैं, लेकिन साहबों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही।

जब इस बदहाली पर शहडोल के जिला परियोजना समन्वयक को घेरा गया, तो उन्होंने जो आंकड़े पेश किए, वे शिक्षा विभाग को पूरी तरह बेनकाब करते हैं। साहब के मुताबिक 83 स्कूल भवन जिले में पूरी तरह जर्जर और संचालन के लायक ही नहीं बचे हैं। 646 जर्जर भवनों को तत्काल मरम्मत की दरकार है, जो कभी भी ढह सकते हैं। 10 स्कूल आज भी निजी भवनों में कंगाली के हाल में चल रहे हैं। 41 स्कूलों में सुधार कार्य अटका है और 20 स्कूलों का प्रस्ताव केवल कागजों पर तैर रहा है। अतरिया स्कूल की यह रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर सूबे की प्राथमिकताओं का असली आईना है। जिन बच्चों के हाथों में सुरक्षित भविष्य होना चाहिए, उन्हें सिस्टम ने मौत के कुएं और गैस सिलेंडर के मुहाने पर धकेल दिया है।

# बिना खाद-बीज दिए किसान के खाते से पैसा पार, कलेक्टर से लगाई गुहार!

**शहडोल।** अन्नदाता को सशक्त बनाने के बड़े-बड़े सरकारी दावों के बीच जिले में आदिम जाति सेवा सहकारी मर्यादित समिति झिंकाबिजुरी के मैनेजर और बैंक कर्मियों की एक रोंगटे खड़े करने वाली जालसाजी सामने आई है। यहां कागजी हेरफेर कर एक गरीब आदिवासी किसान को बिना कोई सामग्री दिए, उसके खाते से हजारों रुपये की अवैध वसूली कर ली गई। इस खुली लूट और तानाशाही से तंग आकर पीड़ित किसान ने अब सीधे जिले के मुखिया की चौखट पर दस्तक

देकर न्याय की भीख मांगी है। ग्राम कुआं जैतपुर के निवासी पीड़ित किसान रामसंजीवन गोंड पिता समरथ गोंड ने कलेक्टर को सौंपे शिकायती पत्र में झिंकाबिजुरी समिति के मैनेजर और संबंधित बैंक पर संगीन आरोप मढ़े हैं। शिकायत के मुताबिक, किसान ने अपनी पत्नी सुमद्रा गोंड के नाम पर बैंक के जरिए केवल 6 बोरी यूरिया खाद लिया था, जिसकी एवज में उसने 1,620 नकद जमा कर वर्ष 2025-26 की बाकायदा रसीद भी प्राप्त कर ली थी, लेकिन असली खेल इसके बाद हुआ। बैंक और समिति के कारिंदों ने जबरन साठगांठ कर किसान के खाते से डीएपी खाद के नाम पर 7,900 और धान के नाम पर 1,120 (ब्याज सहित) की राशि अवैध तरीके से काट ली। पीड़ित किसान रामसंजीवन का साफ कहना है कि उसे समिति से केवल यूरिया मिला था, जबकि डीएपी और धान की कोई खेप उसे दी ही नहीं गई। जब उसने कोई सामग्री ली ही नहीं, तो उसके खाते पर यह डाका क्यों डाला गया? किसान ने सबूत के तौर पर यूरिया की मूल रसीद और परमिट संलग्न करते हुए कलेक्टर से इस पूरे गबन की तत्काल निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस गंभीर मामले ने सहकारी समितियों में चल रहे भ्रष्टाचार और किसानों के नाम पर होने वाली कागजी बंदरबांट को एक बार फिर सरेआम बेनकाब कर दिया है।

## खबर संक्षेप

### दुग्ध समृध्दि संपर्क अभियान का तृतीय चरण 13 से 18 तक

**उमरिया।** पशुपालन एवं डेयरी विभाग व्दारा जिले में दुग्ध संपर्क उत्पादन बढाने एवं पशु पालको को वैज्ञानिक पशुपालन के प्रति जागरूक करने के उददेश्य से दुग्ध समृध्दि संपर्क अभियान का तृतीय चरण आगामी 13 जुलाई से 18 जुलाई तक संचालित किया जाएगा। उप संचालक पशुपालन एवं डेयर विभाग डॉ.एच.पी.शुक्ला ने बताया कि अभियान अंतर्गत जिले के सभी विकासखंडों में कुल 4460 पशु पालक परिवारो तक विभागीय मैदानी अमला पहुंचकर सर्वेक्षण, मार्गदर्शन एवं जागरूकता गतिविधियां संचालित करेगा । इस दौरान पशु नस्ल सुधार की जानकारी दी जाएगी । अभियान के तहत ऐसे पशु पशु पालको को शामिल किया गया है जिनके पास तीन से 4 गौवंश अथवा भैंस वंश है । विभागीय मैदानी अमला घर घर पहुंचकर पशु पालको से सीधे संवाद स्थापित करेगा तथा उन्हे नस्ल सुधार, संतुलित पशु पोषण, हरे चारे के बेहतर प्रबंधन , पशुओ के स्वास्थ्य संरक्षण, मौसली बीमारियों की रोकथाम एवं नियमित टीकाकरण सहित वैज्ञानिक पशु पालन की विभिन्न तकनीको की जानकारी देगा।

### जिले में बीते 24 घंटे में 3.6 मिमी वर्षा दर्ज

**उमरिया।** अधीक्षक भू अभिलेख ने बताया कि बीते 24 घंटे में 3.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। मानपुर तहसील में 2.5 मिमी, पाली तहसील में 3.8 मिमी, नौरोजाबाद तहसील 2.4 मिमी, चंदिया तहसील में 8.2 मिमी, करकेली तहसील में 1.7 मिमी, बिलासपुर तहसील में 7.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। जिले में 1 जून से लेकर 10 जुलाई तक 221 मिमी वर्षा रिकार्ड की गई है जिसमें बांधवगढ़ तहसील में 270.7 मिमी, मानपुर तहसील में 144.6 मिमी, पाली तहसील में 258.2 मिमी, नौरोजाबाद तहसील 251 मिमी, चंदिया तहसील में 169.8 मिमी, करकेली तहसील में 277.3 मिमी, बिलासपुर तहसील में 175.9 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। जबकि गत वर्ष इसी दिनांक तक जिले में कुल 508 मिमी वर्षा रिकार्ड की गई थी जिसमें बांधवगढ़ तहसील में 472.1 मिमी, मानपुर तहसील में 496.8 मिमी, पाली तहसील में 465.6 मिमी, नौरोजाबाद तहसील 454.6 मिमी, चंदिया तहसील में 623.8 मिमी, करकेली तहसील में 426.6 मिमी, बिलासपुर तहसील में 616.8 मिमी वर्षा शामिल है ।

## बाघ होने की आशंका से हडक़ंप

# बांधवगढ़ के बीहड़ों में मिला मांसाहारी वन्यजीव का कंकाल

**उमरिया।** बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक ऐसी खबर आ रही है, जिसने समूचे वन महकमे की रातों की नींद उड़ा दी है। मानसून के दावों और विशेष गश्त के ढोल के बीच, ताला परिक्षेत्र की अति-संवेदनशील मझखेता बीट के घने और दुर्गम जंगलों से एक खौफनाक सच सामने आया है। यहां गश्त कर रही टीम को एक मांसाहारी वन्यप्राणी का सड़-गल चुका कंकाल मिला है। वन्यजीव विशेषज्ञों ने पहली ही नजर में इसके बाघ का कंकाल होने की आशंका जताई है। इस खबर के जंगल की आग की तरह फैलते ही, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से लेकर स्थानीय अमले तक में हडक़ंप मच गया है।

### खोजी कुत्तों और मेटल डिटेक्टर से खंगाला

बांधवगढ़ प्रबंधन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, यह कंकाल 9 जुलाई को मानसूनी गश्त के दौरान मिला। जैसे ही वायरलेस पर यह खबर गूंजी, महकमे के आला अफसरों के हाथ-पांव फूल गए। आनन-फानन में क्षेत्र संचालक, उप संचालक और वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी का काफिला अमले के साथ मौके पर कूच कर गया। मामला देश के सबसे प्रतिष्ठित टाइगर रिजर्व का था, इसलिए किसी भी स्तर पर चूक की गुंजाइश नहीं थी। घटनास्थल की घेराबंदी कर बारीकी से सुराग बटोरे गए। वन विभाग ने कोई भी भौतिक साक्ष्य न छूटे, इसके लिए डॉग स्क्वाड (खोजी कुत्तों) को मैदान में उतारा और आस-पास के चप्पे-चप्पे को खंगाल डाला। यही नहीं, किसी संभावित शिकार या शिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए गए फंदे, गोली या जाल का पता लगाने के लिए मेटल डिटेक्टर से भी जमीन की सघन जांच की गई।

### एनटीसीए प्रोटोकॉल से अग्नि दाह

मौके पर पहुंचे वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी ने प्रथम दृष्टया इसे बाघ का ही कंकाल माना है। हालांकि, प्रजाति और लिंग की अंतिम मुहर वैज्ञानिक लैब की रिपोर्ट के बाद ही लगेगी। हैरान करने वाली बात यह रही कि समयाभाव और आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं का हवाला देकर शव परीक्षण (पोस्टमार्टम) और अंतिम प्रक्रिया को टाल दिया गया। गुरूवार 10 जुलाई को सुबह से ही मझखेता का जंगल छावनी में तब्दील रहा। वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में एनटीसीए के कड़े मानकों और तयशुदा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कंकाल का विधिवत परीक्षण शुरू हुआ। बांधवगढ़ के वन्यजीव स्वास्थ्य अधिकारी और ताला के सहायक पशु चिकित्सा शल्यज्ञ ने संयुक्त रूप से इस रहस्यमयी कंकाल की चीरफाड़ और जांच की। प्रजाति और लिंग का सटीक सच जानने के लिए जरूरी जैविक नमूने (डीएनए सैंपल्स) कलेक्ट किए गए। पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी और दस्तावेजीकरण कर साक्ष्यों को सील किया गया। इसके बाद, नियमों की दुहाई देते हुए इस संदिग्ध कंकाल का अग्नि दहन कर उसे राख में तब्दील कर दिया गया।

### सवाल कई हैं... क्या यह वाकई प्राकृतिक मौत

अफसरों ने भले ही अपनी पीठ थपथपाते हुए बयान जारी कर दिया हो कि पूरी कार्रवाई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों और विधिक प्रावधानों के अनुरूप हुई है, लेकिन स्थानीय गलियारों में चर्चाएं गर्म हैं। फिलहाल वन विभाग वैज्ञानिक परीक्षण की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा कि यह कंकाल बांधवगढ़ के किसी बाघ का है या किसी अन्य मांसाहारी जीव का है। भले ही मानसून की विशेष गश्त का ढिंढोरा पीटा जा रहा हो कि इसका उद्देश्य वन्यजीवों की सुरक्षा और अवैध गतिविधियों पर नकेल कसना है, लेकिन इस घटना ने रिजर्व की सुरक्षा और सतत निगरानी के दावों पर कई गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।

# अपर कलेक्टर ने किया दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्र का निरीक्षण

**उमरिया।** अपर कलेक्टर एवं प्रभारी जिला परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण प्रमोद कुमार सेन गुप्ता ने नगर पालिका परिषद उमरिया द्वारा बस स्टैंड परिसर में संचालित दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रसोई केंद्र में तैयार किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता व्यवस्था, रसोई संचालन, खाद्य सामग्री के रखरखाव तथा रजिस्टर संधारण का बारीकी से अवलोकन किया।

अपर कलेक्टर सेन गुप्ता ने रसोई केंद्र में भोजन कर रहे हितग्राहियों से भी चर्चा की और भोजन की गुणवत्ता, स्वाद तथा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। हितग्राहियों ने शासन की इस जनकल्याणकारी योजना की सराहना करते हुए बताया कि उन्हें मात्र 5 रुपये में पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण

भोजन उपलब्ध हो रहा है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि रसोई केंद्र में स्वच्छता, भोजन की गुणवत्ता और समय पर भोजन वितरण की व्यवस्था निरंतर बनाए रखें, ताकि जरूरतमंदों को बेहतर सुविधाएं मिलती रहें। निरीक्षण के दौरान सईद मंसूरी, वीरेंद्र एवं निशांत मिश्रा भी उपस्थित रहे।

# विश्व जनसंख्या दिवस आज मनाया जाएगा

**उमरिया।** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर व्ही एस चंदेल ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा । भारत शासन से प्राप्त दिशा निर्देश अनुसार इस वर्ष 11 जुलाई से 18 जुलाई 2026 तक विश्व जनसंख्या दिवस अभियान मनाया जाना है। अभियान का उद्देश्य सही समय पर गर्भावस्था तथा दो बच्चों के मध्य सही समय के अंतर को शैक्षिक साधनों के उपयोग से बढ़ावा देना है जिससे मातृ स्वास्थ्य एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके । नोडल अधिकारी डॉ.संदीप सिंह ने बताया कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत इस वर्ष की थीम अनुसार मां और बच्चे की अच्छी सेहत के लिए गर्भधारण के लिए सही समय तथा गर्भावस्था के माध्यम सही अंतर रखना जरूरी है। परिवार नियोजन सेवाओं के जिला चिकित्सालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अन्य सभी स्वास्थ्य संस्थानों के साथ साथ ग्राम स्तर पर चिन्हित सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे । उन्होंने बताया कि आशा कार्यकर्ता के द्वारा परिवार नियोजन के साधनों की मांग अनुसार उपलब्धता बनाए रखें जिससे कि हितग्राहियों को साधन आसानी से उपलब्ध हो सके। उन्होंने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए आशा कार्यकर्ता के माध्यम से व्यक्तिगत संपर्क कर चिन्हित दंपतियों को प्रेरित करना सुनिश्चित किया जाएगा जिसमें सास बहू सम्मेलन राज्य से प्राप्त निर्देशों के अनुसार किया जाएगा । नोडल अधिकारी डॉक्टर संदीप सिंह ने बताया कि परिवार नियोजन संदेशों एवं प्रचार प्रसार किया जाना अति आवश्यक है जिसमें शहरी एवं ग्रामीण अंचल के स्वास्थ्य कार्यकर्ता सक्रियता के साथ इस अभियान को सफल बनाएंगे । उन्होंने बताया कि परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों हेतु सरकार की ओर से भी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है जिसमें प्रसव के 6 सप्ताह बाद आयुसीडी, प्रसव उपरांत आयु सीडी का उपयोग, गर्भ निरोधक इंजेक्शन अंतर, गर्भनिरोधक गोलियां आपातकालीन गोलियां, परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि निश्चित सेवा दिवस जिसके तहत विकासखंड एवं जिला स्तर पर कैलेंडर तैयार कर नसबंदी सेवाओं का लाभ हितग्राही प्राप्त कर सकते हैं।

## कोतमा के कमल किशोर पटेल बने माइनिंग इंस्पेक्टर

### एमपीपीएससी में 27वीं रैंक हासिल कर बढ़ाया जिले का मान

**कोतमा।** कोतमा नगर के वार्ड क्रमांक 7 निवासी युवा कमल किशोर पटेल ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) की परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करते हुए 27वीं रैंक प्राप्त की है। इस उपलब्धि के साथ उनका चयन माइनिंग इंस्पेक्टर पद पर हुआ है। उनकी इस सफलता से न केवल कोतमा नगर बल्कि पूरे अनूपपुर जिले में खुशी और गौरव का माहौल है। कमल किशोर पटेल, पिता रज्जन प्रसाद पटेल, ने यह सफलता अपने दूसरे प्रयास में हासिल की। उन्होंने कठिन परिश्रम, अटूट आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के बल पर यह मुकाम प्राप्त किया। उनकी सफलता उन युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यह उपलब्धि साबित करती है कि निरंतर मेहनत, धैर्य और लक्ष्य के प्रति समर्पण से किसी भी कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की जा सकती है। कमल किशोर की इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर नगर के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, इष्ट मित्रों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। सभी ने विश्वास जताया कि वे अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन कर प्रदेश और जिले का नाम आगे भी रोशन करेंगे।

## 23 स्कूली वाहनों की जांच, 12 पर कार्रवाई, 22,500 रुपये का जुर्माना

### दोबारा जांच में फिर मिली लापरवाही, बिना परमिट दौड़ रहे दो स्कूल वाहन पकड़े गए

**कोतमा।** जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक विक्रांत मुराब के निर्देशन में संचालित सुरक्षित स्कूल बस अभियान 3.0 के तहत जिला यातायात पुलिस द्वारा लगातार सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान शुक्रवार को विभिन्न विद्यालयों में संचालित 23 स्कूली बसों एवं अन्य वाहनों की जांच की गई। जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 12 वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 22,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जिला यातायात प्रभारी विनोद दुबे ने बताया कि जांच के दौरान महर्षि एंग्लो जर्मन स्कूल, अनूपपुर की बस तथा ग्रीनलैंड स्कूल, कोतमा के बच्चों को ले जा रहा वाहन बिना वैध परमिट के संचालित पाया गया। दोनों वाहनों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा अन्य कई वाहनों में आवश्यक दस्तावेजों एवं सुरक्षा मानकों से जुड़ी कमियां मिलने पर भी चालानी कार्रवाई की गई। अभियान के अंतर्गत ग्रीनलैंड स्कूल कोतमा, एसएसआर इंटरनेशनल स्कूल पयारी, बैथल मिशन स्कूल अनूपपुर, डीवीएम स्कूल अनूपपुर, सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय अनूपपुर तथा कल्याणिका विद्यालय राजेंद्रग्राम में संचालित स्कूली वाहनों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान बसों के परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र, अग्निशामक यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, इमरजेंसी एग्जिट, आवश्यक दस्तावेज तथा अन्य सुरक्षा मानकों का बारीकी से परीक्षण किया गया। जिला यातायात प्रभारी विनोद दुबे ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना भी है। इसी क्रम में विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही बस चालकों को निर्धारित गति सीमा का पालन करने, वाहन का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने तथा बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिम्मेदारीपूर्वक वाहन संचालन करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सुरक्षित स्कूल बस अभियान 3.0 आगे भी लगातार जारी रहेगा और नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूल वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि जिले के सभी स्कूली बच्चों को सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराया जा सके।

# समय से पहले बंद हो रहा स्कूल, बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा असर

**बेलिया बड़ी प्राथमिक विद्यालय में निर्धारित समय से पहले छुट्टी का आरोप**

### ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की उठाई मांग

**कोतमा।** शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और सरकारी विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के सरकार के दावों के बीच कोतमा विकासखंड के शासकीय प्राथमिक विद्यालय बेलिया बड़ी से सामने आई स्थिति इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों का आरोप है कि विद्यालय में निर्धारित समय से पहले ही छुट्टी कर दी जाती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार शिक्षा विभाग के नियमों के तहत शासकीय विद्यालयों का संचालन सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक होना चाहिए, लेकिन बेलिया बड़ी प्राथमिक विद्यालय में कई दिनों से दोपहर करीब 3 बजे ही बच्चों की छुट्टी कर विद्यालय बंद कर दिया जाता है। इससे बच्चों की नियमित पढ़ाई प्रभावित हो रही है और अभिभावकों में नाराजगी बढ़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब उन्होंने विद्यालय में मौजूद शिक्षकों से समय से पहले छुट्टी करने का कारण पूछा तो उन्हें स्कूल की व्यवस्थाओं का हवाला दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि किसी प्रकार की समस्या है तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी जानी चाहिए, न कि बच्चों की

पढ़ाई प्रभावित की जाए। मामले की जानकारी लेने पर संकुल प्रभारी ने बताया कि उन्हें विद्यालय समय से पहले बंद किए जाने की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि यदि विद्यालय निर्धारित समय से पहले बंद किया गया है तो यह नियमों के अनुरूप नहीं है। वहीं विद्यालय में मौजूद शिक्षकों ने बताया कि प्राचार्य अवकाश पर हैं। विद्यालय के कुछ छात्रों ने भी बताया कि समय से पहले छुट्टी होना कोई नई बात नहीं है, बल्कि ऐसा अक्सर होता है। यदि यह तथ्य जांच में सही पाए जाते हैं तो इससे स्पष्ट होगा कि बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीणों और अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा यदि अनियमितता प्रमाणित होती है तो संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकारी विद्यालयों में इस तरह की लापरवाही बच्चों के भविष्य के साथ समझौता है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अब सभी की नजर शिक्षा विभाग पर है कि शिकायत की जांच किस प्रकार की जाती है और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाती है।

## अमृत हरित महाअभियान के तहत नगर परिषद बनगवां में 700 पौधों का वृहद वृक्षारोपण

### हरियाली बढ़ाने का संकल्प, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने लिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

**राजनगर।** अमृत हरित महाअभियान के अंतर्गत नगर परिषद बनगवां (राजनगर) द्वारा शुक्रवार को वार्ड क्रमांक-14 स्थित प्रेमनगर कॉलोनी के पीछे खेल मैदान परिसर में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी लखन लाल पनिका के निर्देशन में आयोजित इस अभियान की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष यशवंत सिंह ने की। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, नगर परिषद के अधिकारियों-कर्मचारियों एवं स्थानीय नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अभियान के दौरान लगभग 700 फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण किया गया। नगर परिषद को केंद्र शासन द्वारा 12 हजार तथा राज्य शासन द्वारा 1 हजार पौधों के रोपण का लक्ष्य दिया गया है। परिषद के अनुसार अब तक नगर क्षेत्र में 2300 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं और आगामी दिनों में यह अभियान लगातार जारी रहेगा। नगर परिषद अध्यक्ष यशवंत सिंह ने बताया कि परिषद क्षेत्र में कोयला खदानों की अधिग्रहित भूमि एवं वन विभाग के अधीन क्षेत्रों के कारण वृक्षारोपण के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसके बावजूद परिषद उपलब्ध स्थानों का चयन कर अधिक से अधिक पौधे लगाने का प्रयास कर रही है, ताकि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जा सके और क्षेत्र में हरित आवरण बढ़ाया जा सके। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए सभी से अधिक से अधिक पौधे लगाने एवं उनकी देखभाल करने का आह्वान किया गया। वक्ताओं ने कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण संतुलन ही नहीं बनाए रखते, बल्कि शुद्ध वायु, वर्षा, जल संरक्षण, मिट्टी संरक्षण तथा जैव विविधता को भी सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वृक्षों से मिलने वाली हरियाली मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होती है। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष कमलेश चतुर्वेदी, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेश गौतम, महामंत्री सचिन द्विवेदी, नारायण साहू, सांसद प्रतिनिधि एवं पत्रकार मनोज सिंह, मंडल मीडिया प्रभारी पंकज कुमार शर्मा, नगर परिषद के पार्षद, अधिकारी-कर्मचारी, गणमान्य नागरिक, वार्डवासी तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

### 11 जुलाई तक सत्यापन पूरा करने के निर्देश

**कटनी।** ग्रामीण क्षेत्रों में आवास से वंचित पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ सुनिश्चित करने के लिए "आवास प्लस 2024" सर्वे की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में जिले में प्रारूप स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) के अंतिमकरण एवं ग्राम सभा सत्यापन की कार्यवाही तेज कर दी गई है। पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के संचालक दिनेश जैन ने स्व-सर्वे पुष्टि, चेकर सत्यापन तथा अपात्र परिवारों को सूची से हटाने की प्रक्रिया 11 जुलाई 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद ही सिस्टम द्वारा जनरेटेड प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 3 एवं 4 जुलाई को पोस्ट डिलीशन मॉड्यूल के संबंध में मैदानी अमले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

## खबर संक्षेप

### कृषि उपज मंडी और गौशाला नहीं होने से परेशानी

**सिलौंडी।** सिलौंडी जो कि 84 गांव का मुख्य व्यापारिक स्थान है। सिलौंडी में किसानों और व्यापारियों की मांग पर तत्कालीन कलेक्टर अवि प्रसाद ने कृषि उपज मंडी और गौशाला निर्माण की स्वीकृत प्रदान करते हुए नेगाई में शासकीय भूमि में चिन्हित कराया था परंतु भूमि चिन्हित होने के बाद भी अभी तक निर्माण कार्य शुरू नही हुआ है जिसके कारण आवारा पशु के कारण किसानों की फसल चौपट हो रही है। कृषि उपज मंडी नही बनाने के कारण किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नही मिल रहा है 25 से 30 किलोमीटर दूर मंडी ले जाने से भाड़ा और अन्य खर्च नही कर पाने के कारण वह मजबूरी में कम दाम में फसल बेच रहा है। व्यापारियों को भी अपने उत्पाद बेचने के लिए लंबी दूरी जाना पड़ रहा है।
जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन की बेपरवाही से विकास के कार्यों में पीछे हो रहा है । सिलौंडी में मूल भूत सुविधा ना होने के कारण लोग अन्य स्थान से खरीदी कर रहे है जिसके सिलौंडी व्यापारिक गतिविधियों में पीछे जा रहा है ।

### पेंशन एवं सेवा संबंधी समस्या निवारण शिविर

**कटनी।** निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार द्वारा निगम में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारियों की पेंशन एवं सेवा संबंधी समस्याओं के पारदर्शी एवं समयबद्ध निराकरण हेतु समस्या निवारण शिविर आयोजित करने के दिए गए निर्देशों के परिपालन में निगम कार्यालय के कक्ष क्रमांक- 44 में पेंशन एवं सेवा संबंधी समस्या निवारण शिविर आयोजित किया जायेगा ।
शिविर के दौरान निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार की मौजूदगी में अधिकारी-कर्मचारियों की पेंशन, परिवार कल्याण निधि, ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी., जी.पी.एफ., एन.पी.एस., यू.ए.एन. तथा विधिक मामलों सहित सेवा संबंधी विभिन्न समस्याओं पर सुनवाई की जाकर आवश्यकता अनुसार संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी, जिससे पात्र कर्मचारियों को समय पर राहत मिल सके। निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शिविर में प्राप्त प्रत्येक प्रकरण का गंभीरता, संवेदनशीलता एवं उत्तरदायित्व के साथ निराकरण किया जाए तथा किसी भी पात्र कर्मचारी या पेंशनर के प्रकरण में अनावश्यक विलंब न होने दिया जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों एवं पेंशनरों की समस्याओं का त्वरित समाधान निगम प्रशासन की प्राथमिकता है।

### मुक्तिधाम में अतिक्रमण का आरोप, कार्रवाई की मांग

**उमरियापान।** ढीमरखेड़ा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत देवरी पाठक के तिघरा गांव में बने मुक्तिधाम और उससे लगी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने पंचायत और राजस्व अधिकारियों से शिकायत कर अतिक्रमण हटाने तथा संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के महेन्द्र सिंह ने मुक्तिधाम परिसर और उसके आसपास की भूमि पर कब्जा कर लिया है। मुक्तिधाम में बने शेड का उपयोग पालतू मवेशियों को बांधने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा मुक्तिधाम से लगी भूमि की जुताई भी करा दी गई है, जिससे सार्वजनिक उपयोग की इस जगह की उपयोगिता प्रभावित हो रही है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि मुक्तिधाम गांव की सार्वजनिक संपत्ति है, लेकिन अतिक्रमण के कारण अंतिम संस्कार जैसे कार्यों में भविष्य में परेशानी खड़ी हो सकती है। ग्रामीणों ने जांच कर अतिक्रमण हटाने की मांग की है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत करने पर कब्जे के आरोपी द्वारा गाली-गलौज कर डराया-धमकाया जा रहा है। पंचायत के जिम्मेदारों का कहना है कि कब्जा करने वाले व्यक्ति से बातचीत कर मुक्तिधाम शेड से मवेशियों को अलग करने कब्जा हटाने कहा गया है।

---

हर वार्ड से उठ रही शिकायतें, दोपहिया चालक फिसल रहे, वाहन कीचड़ में फंस रहे; नगर पालिका और ठेकेदार की कार्य प्रणाली पर सवाल

# पाइप लाइन विस्तार की खुदाई बनी जानलेवा अधूरी भराई से बरसात में धंस रहीं सड़कें

**धनपुरी।** नगर पालिका क्षेत्र में करोड़ों रुपये की लागत से चल रहे पेयजल पाइपलाइन विस्तार कार्य का उद्देश्य भले ही हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना हो, लेकिन निर्माण कार्य में बरती जा रही लापरवाही अब आम नागरिकों के लिए परेशानी और खतरे का कारण बन गई है। पाइपलाइन बिछाने के बाद गड्ढों की समुचित भराई नहीं होने से नगर की सड़कें बरसात में जगह-जगह धंस रही हैं। कीचड़ और दलदल के कारण रोजाना छोटे-छोटे हादसे हो रहे हैं, जबकि लोगों में किसी बड़े हादसे की आशंका भी बढ़ गई है। नगर के विभिन्न वार्डों से लेकर मुख्य मार्गों तक पाइपलाइन डालने के लिए सड़कें खोदी गईं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि पाइप डालने के बाद गड्ढों को मानकों के अनुरूप दबाया और समतल नहीं किया गया। केवल मिट्टी डालकर कार्य पूरा दिखा दिया गया। अब लगातार हो रही बारिश से वही मिट्टी बह रही है और सड़कों के नीचे खाली जगह बनने से मार्ग धंसने लगे हैं।
सबसे अधिक परेशानी दोपहिया वाहन चालकों को हो रही है। बारिश के पानी से भरे गड्ढों की गहराई का अनुमान नहीं लग पाने से लोग फिसलकर गिर रहे हैं। कई स्थानों पर चारपहिया वाहन भी दलदल में फंस रहे हैं,

जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और पैदल राहगीरों को भी जोखिम उठाकर निकलना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पाइपलाइन विस्तार कार्य में गुणवत्ता की अनदेखी की जा रही है। नगर पालिका और निर्माण एजेंसी की निगरानी भी सवालों के घेरे में है। यदि गड्ढों की भराई सही ढंग से की जाती और सड़क को पहले जैसी मजबूती से बहाल किया जाता, तो आज लोगों को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता।
नगरवासियों ने मांग की है कि जिन स्थानों पर पाइपलाइन कार्य पूरा हो चुका है, वहां तत्काल मजबूत भराई कर सड़क की मरम्मत कराई जाए। साथ ही लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाए, ताकि विकास कार्य लोगों के लिए सुविधा बनें, परेशानी नहीं।
लोगों का कहना है कि पेयजल योजना का लाभ तभी सार्थक होगा, जब उसके साथ नागरिकों की सुरक्षा और आवागमन की सुविधा भी सुनिश्चित की जाए। बरसात के इस मौसम में नगर पालिका को केवल निर्माण कार्य पूरा कराने के बजाय उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा।

---

# थाने में खड़ा लकड़ी से लोड ट्रक

**लकड़ी के ट्रक को एसडीएम द्वारा खड़ा कराया गया है आप उन्हीं से जानकारी ले सकते हैं- जिया उल हक थाना प्रभारी ब्यौहारी**

**ब्यौहारी।** थाना ब्यौहारी के अंतर्गत ग्राम पसगडी के निवासी सुभाष कुमार मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर मांग किया कि उनके यहां कई लाख की चोरी हो गई जिसकी रिपोर्ट उनके द्वारा थाने में दर्ज कराएगे। थाना व्यवहारी में एफ आई आर क्रमांक 0409/26 के दिनांक 11/06/26 को दर्ज हुआ है। प्रकरण दर्ज करने के बाद पुलिस द्वारा जिसको जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है उनके द्वारा अनावश्यक विलंब किया जाता रहा है एवं जिन संदेहियों का फिंगरप्रिंट लेने के लिए नाम बताए गए उनका फिंगर प्रिंट नहीं लिया जा रहा है उनको थाने बुलाकर के छोड़ दिया जाता है और फिंगर प्रिंट नहीं लिया जाता जिससे महत्वपूर्ण तथ्य छूटे जा रहे जिससे इतनी बड़ी हुई चोरी में में संदेह बढ़ता जा रहा है। मोबाइल लोकेशन,फिंगर प्रिंट शीघ्र लिए जायें यदि इसी तरह से अनावश्यक विलंब किया जाएगा तो चोरी का खुलासा कैसे होगा। आवेदक ने जांच अधिकारी के रवैया पर सवाल उठाया है कि आखिर उनके द्वारा इस तरह से ढुलमुल रवैया क्यों अपनाया जा रहा है आवेदक ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत कर जांच अधिकारी बदलने की मांग की है।

# राजस्व क्षेत्र से हो रही लगातार पेड़ों की कटाई

**ब्यौहारी।** थाना क्षेत्र ब्यौहारी- के अंतर्गत तगावर एवं टिहकी के राजस्व क्षेत्र से लगातार पेड़ों को काटा जा रहा है जिससे पर्यावरण प्रभावित हो रहा है करीब 15 दिन पहले लकड़ी से भरा एक ट्रक एसडीएम द्वारा तगावर से पकड़ा गया बाद में कार्रवाई के बाद छोड़ दिया गया उसके बाद फिर से राजस्थान नंबर का एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें यूके लिप्टिस लोड है जो पिछले तीन दिनों से थाने में खड़ा हुआ है बड़ा सवाल यह उठता है कि बड़ी संख्या में पेड़ राजस्व की जमीन पर भी है और वहां से लगातार अवैध तरीके से पेड़ कट रहे हैं राजस्व के अधिकारियों द्वारा यह ध्यान नहीं दिया जाता की बड़ी संख्या में पेड़ काटने से पर्यावरण प्रभावित हो रहा है काफी उम्र दराज पेड़ भी काटे जाते हैं निजी जमीन में पेड़ काटने की अनुमति ग्राम पंचायत को दे दी गई है जिसके तहत सरपंच द्वारा सादे कागज में ही पेड़ काटने की अनुमति दे दी जाती है आजकल पंचायत द्वारा ऑनलाइन अनुमति दर्पण पोर्टल के माध्यम से होनी चाहिए यदि ऑनलाइन अनुमति नहीं है तो वह गलत है सरपंच को क्या पता कि जिस

आराजी में वह लकड़ी काटने की अनुमति दे रहे हैं उसमें पेड़ दर्ज है या नहीं इसके अलावा किसान द्वारा भी पटवारी से सेटिंग कर उस आराजी में पेड़ दर्ज कर लिया जाता है और यदि दो पेड़ काटने की अनुमति है तो उसके आसपास के सैकड़ो पेड़ काट दिए जाते हैं बुढ़वा क्षेत्र में भी हजारों पेड़ काटे गए हैं जिससे पर्यावरण को बहुत खतरा है वर्तमान में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लकड़ी माफिया जयसिंहनगर के तगावर,टिहकी और आसपास के क्षेत्र में सक्रिय और यहां राजस्व की जमीन से लकड़ी काटकर लगातार अवैध रूप से बेंचा जा रहा है 15 दिन पहले जो लकड़ी पकड़ी गई थी उसको ले जाने के लिए टीपी की जरूरत थी लेकिन वन विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वन विभाग से टीपी नहीं ली गई तो आखिर लकड़ी कैसे चली गई यह बड़ा सवाल उठ रहा है राजस्व के अधिकारियों को भी ध्यान देना होगा कि उनके क्षेत्र के पेड़ सुरक्षित रहें और लकड़ी माफिया पर लगाम लगाना होगा।

---

# स्लीमनाबाद पहुंचकर एसपी ने टनल निर्माण का लिया जायजा

हरिभूमि न्यूज ⏭ स्लीमनाबाद

बरगी व्युत्पर्जन परियोजना के तहत स्लीमनाबाद में अंडर ग्राउंड टनल का निर्माण कार्य चल रहा हैं, जो लगभग 15 वर्षो के बाद अब पूर्णता की ओर हैं। 11.95 किलोमीटर लंबी सुरंग में अब सिर्फ 40 मीटर खुदाई शेष हैं। 15 जुलाई तक टनल निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद हैं। इसके बाद नर्मदा जल से 5 जिलों की 1.85 लाख हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी। टनल निर्माण कार्य जैसे जैसे पूर्णता की ओर आ रही हैं वैसे ही जनप्रतिनिधियों व अधिकारियो के द्वारा टनल निर्माण स्थल का दौरा किया जा रहा हैं। दो दिवस पूर्व जहाँ सतना सांसद गणेश सिंह ने निरीक्षण किया था तों गुरुवार को कटनी एसपी अभिनय विश्वकर्मा ने टनल निर्माण स्थल का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने टनल निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों से कार्य की वर्तमान स्थिति, सुरक्षा व्यवस्थाओं तथा निर्माण कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

# ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत आवास प्लस 2024 सर्वे के तहत प्रारूप स्थायी प्रतीक्षा सूची (Draft PWL) के अंतिमकरण एवं ग्राम सभा सत्यापन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए जिले के सभी ग्रामों में 9 एवं 10 जुलाई को दो दिवसीय ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देशानुसार आयोजित इन ग्राम सभाओं में एजेंडा के बिंदु क्रमांक 03 से 06 तक की कार्यवाही अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएगी। ग्राम सभाओं का संचालन पूर्व से नियुक्त स्थायी नोडल अधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा तथा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरी प्रक्रिया संपादित की जाएगी। कलेक्टर श्री तिवारी ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्राम सभाओं का आयोजन सुव्यवस्थित एवं सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर विशेष परिस्थितियों में नोडल अधिकारियों में संशोधन करते हुए कार्यवाही पूर्ण कराई जाएगी।

---

# आटो में छूटा लैपटॉप, सीसीटीवी की मदद से किया बरामद, यात्री को वापस लौटाया

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

आटो में गंतव्य तक पहुंचने के लिये यात्रा के दौरान एक व्यक्ति का लैपटॉप वाहन में ही छूट गया जिसे पुलिस की तत्परता से बरामद कर वापस लौटाया गया। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य के मार्गदर्शन में संचालित सीसीटीवी मॉनिटरिंग के तहत यह सफलता मिली।
फरियादी घनेन्द्र कुमार त्रिपाठी और उनकी पुत्री शालिनी तिवारी ने पुलिस को बताया कि वे दुर्गा चौक से थाना तिराहा जाने के लिए ऑटो में सवार हुए थे, जहां यात्रा के दौरान उनका लैपटॉप ऑटो में ही छूट गया।सूचना मिलते ही सीसीटीवी टीम ने बताए गए मार्ग के कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच में खिरहनी ब्रिज और थाना तिराहा के कैमरों में संबंधित ऑटो दिखाई दिया, जिसके आधार पर वाहन का पंजीयन क्रमांक एमपी-21 जेडबी-7850 चिन्हित किया गया।आरटीओ रिकॉर्ड से चालक की जानकारी प्राप्त कर उससे संपर्क किया गया।
चालक ने बताया कि लैपटॉप उसके पास सुरक्षित रखा हुआ है। इसके बाद थाना एनकेजे पुलिस और सीसीटीवी टीम ने लैपटॉप प्राप्त कर फरियादी को विधिवत सुपुर्द कर दिया।लैपटॉप सुरक्षित वापस मिलने पर फरियादी और उनके परिजनों ने कटनी पुलिस की संवेदनशीलता एवं त्वरित कार्रवाई की सराहना की।
इस कार्य में दीक्षा रेडियो की अनामिका सोनकर, मृदुल त्रिपाठी, देवराज सिंह, पुष्पेंद्र यादव तथा थाना एनकेजे पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

# सौतेले भाई की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बरही थाना अंतर्गत कुटेश्वर क्षेत्र में दो वर्ष हुए हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। मीडिया सेल प्रभारी सुरेन्द्र कुमार गर्ग ने बताया कि 30 जुलाई 2024 को फरियादी 42 वर्षीय संतोष यादव ने थाना बरही में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 29 जुलाई 2024 को मेरी पहली पत्नी का लडक़ा मनीष यादव काम करने बिना बताये बाहर चला गया है एवं दूसरी पत्नी का लडक़ा सुमित यादव भी उसी समय से घर में नहीं था। मैं मवेशी चराने गया था जब शाम लगभग 6 बजे घर आया तो परिवार के लोग बताये कि सुमित यादव कहीं चला गया है तब उसकी तलाश पतासाजी आस पड़ोस में व गांव एवं रिश्तेदारियों में फोन से पता किया। सुमित यादव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बडे लडक़े मनीष यादव को रात में कई बार फोन लगाये तो वह फोन नही उठाया। फिर जब सुबह मनीष से बात हुई तो बताया कि काम करने अहमदाबाद आ गया हूं, सुमित यादव मेरे पास नही हैं। मुझे शंका है कि मेरे लडके सुमित को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर कहीं भगा ले गया है।
रिपोर्ट पर अपराध पंजीबध्द किया गया। मुखबिर की सूचना पर संदेही मनीष यादव 20 साल को 31 जुलाई 24 को दस्तयाब कर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ में मनीष ने बताया कि मेरे पिता संतोष यादव जिनकी दो शादियां हुई हैं। सौतेली मां कमला को तीन लड़कियां व एक लडक़ा जिसका नाम सुमित उर्फ मोनू यादव 12 वर्ष का है। ये लोग पिता जी के साथ रहते हैं। पिताजी हम लोगो की कोई मदद नहीं करते है न हमे चाहते हैं। अक्सर मुझसे व मेरे परिवार से झगड़ा करते हैं। हम लोगो को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करते है। इन सब बातो को लेकर मेरे मन में खुन्नस भरी थी।
मनीष ने बताया कि 29 जुलाई 2024 को दोपहर मैं पुराने घर आया जहां पर मुझे मोनू उर्फ सुमित मिला और गाली गलौज करने लगा, जिससे मुझे गुस्सा आ गया। मेरे मन में पहले से खुन्नस भरी थी तो मैने अपने गमछे से उसका गला दबाकर मार दिया जिसे मैं मोर्चा मोड में पगरा रोड (बंजरिया) पहाड़ी की झाड़ी में फेक आया। पूछताछ करने के बाद मनीष के निशानदेही पर मोर्चा मोड़ पगरा रोड बंजरिया पहाड़ी की झाड़ी में तलाश दौरान अपहृत बालक सुमीत यादव का शव बरामद किया गया। पीएम के बाद मनीष के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामला सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश किया गया।
प्रकरण में विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय के समक्ष समस्त सारवान साक्षी, दस्तावेज एवं वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत कर आरोपी के विरुद्ध आरोप प्रमाणित कराया गया। विशेष लोक अभियोजक के लिखित तर्कों से सहमत होते हुये न्यायालय द्वारा आरोपी मनीष यादव को हत्या करने के अपराध पर आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।

---

**सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चलाया जागरूकता अभियान**

# साइबर ठगी से बचने के लिए बरतें सावधानी, रहे जागरूक

हरिभूमि न्यूज ⏭ स्लीमनाबाद

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्लीमनाबाद में साइबर सुरक्षा को लेकर सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। थाना प्रभारी सुदेश सुमन ने डॉक्टरों, अस्पताल स्टॉफ एवं आमजनों को जागरूक करते हुए कहा कि आजकल लालच व अज्ञानतावश लोग साइबर अपराध का शिकार हो रहे हैं। साइबर ठगी का शिकार लोगों की फेहरिस्त में बड़े उद्यमी-कारोबारी, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी से लेकर सरकारी कर्मचारी, पुलिस महकमे के लोग और बैंक अधिकारी तक शामिल हैं, जो शिक्षित हैं और बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते रहे हैं या कर रहे हैं। लेकिन सावधानी नहीं बरतने पर वे साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। यानी साइबर ठग किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, वे समाज के हर वर्ग को चंगुल में ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि साइबर ठगी करने वाले पहले फर्जी कॉल कर प्रलोभन देते हैं। जिसके जरिए वे बैंक डिटेल, आधार या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर लेते हैं और फिर खाते रुपए पार कर लेते हैं। इसके अलावा थाना प्रभारी द्वारा अन्य साइबर अपराधों से बचने के प्रभावी उपाय बताए साथ ही किसी भी संदिग्ध कॉल, संदेश या ऑनलाइन लेनदेन के प्रति सतर्क रहने की अपील की अभियान के दौरान लोगों को साइबर अपराधों से बचाव के लिए जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है के बारे मे अवगत कराया गया एवं किसी के साथ साइबर ठगी होती है तो तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करने हेतु जागरूक किया गया ।साथ ही बताया कि फोन पर कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को बिना सोचे समझे क्लिक न करें। यदि आपके साथ कोई साइबर क्राइम या कोई अनचाही स्थिती बने तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। ऐसे में साइबर अपराध को रोकने के लिए विशेष सतर्कता के साथ आधुनिक तकनीक का ज्ञान होना आवश्यक है। सतर्क रहकर ही इस अपराध से बचा जा सकता है।क्योंकि सुविधाएं कई बार समस्या भी बन जाती है। ऐसे में जागरूकता ही बचाव है। आजकल सारे काम ऑनलाइन होने लगे हैं। इसलिए सावधानी की सख्त आवश्यकता है। कोई भी ऑनलाइन कार्य करें तो किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को ओटीपी नहीं देवें।

# राशन दुकान के पास गंदगी का अंबार फिसलन एवं बदबू से उपभोक्ता परेशान

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 3 की शासकीय उचित मूल्य की दुकान रानी दुर्गावती महिला प्र.उप.भंडार के पास गंदगी का अंबार लगा है। खाद्यान्न लेने यहां सैकड़ों उपभोक्ता पहुंचते हैं। राशन दुकान के आसपास कचरा और बजबजाती गंदगी से न सिर्फ दुर्गंध से सांस लेना दूभर हो रहा है बल्कि फिसलन से हादसे की आशंका बनी रहती है। राशन दुकान के विक्रेता केशव कुशवाहा का कहना है कि हल्की बारिश में ही गंदा पानी दुकान के अंदर घुस जाता है जिससे न सिर्फ परेशानी होती है बल्कि यहां खाद्यान्न लेने पहुंचने वाले हितग्राहियों को भी हादसे का डर बना रहता है।
विक्रेता केशव कुशवाहा का कहना है कि इस समस्या के बारे में मेरे द्वारा कई बार वार्ड पार्षद को कई बताया गया लेकिन आज तक न तो साफ सफाई कराई गई और न ही पानी की निकासी की व्यवस्था दुरूस्त कराई गई। राशन दुकान के सामने गंदगी से न सिर्फ दुर्गंध बनी रहती है बल्कि कीचड़ की वजह से फिसलन बढ़ जाती है जिससे कई बार लोग फिसलकर गिर भी पड़ते हैं। विक्रेता ने बताया कि खाद्यान्न लेने पहुंचने वाले हितग्राहियों की भीड़ दिन भर बनी रहती है। वर्षाकाल के मौसम में बारिश के चलते दुकान के अंदर गंदा पानी घुस जाता है जिससे खाद्यान्न सामग्री के भी बर्बाद होने की संभावना बनी रहती है। जल निकासी एवं सफाई की व्यवस्था कराने की मांग की है।

# दोनों राज्यों में हाथी एक जैसे, तो मुआवजा में भेदभाव क्यों?

## आखिर मध्य प्रदेश के ग्रामीणों को छत्तीसगढ़ जैसी राहत क्यों नहीं?

अनूपपुर जिले के जैतहरी क्षेत्र के दर्जनों गांव वर्षों से हाथियों के आतंक का सामना कर रहे हैं। हर साल खेत उजड़ते हैं, मकान टूटते हैं और लोगों की रातें डर के साये में गुजरती हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में प्रभावित परिवारों को बेहतर मुआवजा दिया जा सकता है, तो मध्य प्रदेश के ग्रामीणों को बराबरी का अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहा है? अब इस मुद्दे पर आवाज तेज होने लगी है और लोग बेसब्री से अपने जनप्रतिनिधियों की ओर टकटकी लगाए बैठे है।

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।

जिले के जैतहरी क्षेत्र के चोलना, चोई, पड़रिया, लहरपुर, बेलिया, बरबसपुर, खैरहा, डोला सहित कई गांव हाथियों के नियमित आवागमन वाले इलाके में आते हैं। यहां हर वर्ष किसानों की फसल बर्बाद होती है और कई परिवारों के कच्चे मकान हाथियों के हमले में टूट जाते हैं। इसके बाद शुरू होती है सरकारी प्रक्रिया, जिसमें राहत मिलने का इंतजार महीनों तक चलता रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि मिलने वाला मुआवजा नुकसान के मुकाबले बहुत कम है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सरकार ने मकान क्षति पर 1.20 लाख से 1.30 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान किया है। इसी आधार पर युवा नेता सत्यनारायण राठौर के साथ ग्रामीणों ने मांग उठाई है कि मध्य प्रदेश में भी समान नीति लागू किया जाना चाहिए जिसके लिए

सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से अनुरोध किया गया है। यह केवल आर्थिक सहायता का मामला नहीं है, बल्कि उन परिवारों के सम्मान और सुरक्षा का भी प्रश्न है जो हर दिन हाथियों के बीच जीवन बिताने को मजबूर हैं।

### सीमा बदली, लेकिन दर्द क्यों अलग?

जैतहरी के कई गांव छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हैं। जंगल, हाथी और नुकसान दोनों राज्यों में लगभग एक जैसे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि छत्तीसगढ़ में राहत ज्यादा है, जबकि मध्य प्रदेश में प्रभावित परिवार कम मुआवजे में ही गुजारा करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का सवाल सीधा है कि जब परेशानी समान है तो राहत की नीति अलग-अलग क्यों है? सरकार को इस अंतर को खत्म कर समान व्यवस्था लागू करनी चाहिए।

### हाथी हर साल आते हैं, लेकिन राहत समय पर नहीं

जिले में हाथियों के आने का सिलसिला अब कोई नई बात नहीं रह गया है। हर साल खेतों की फसल नष्ट होती है और कई मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसके बावजूद राहत राशि मिलने में लंबा समय लग जाता है। कई परिवारों को अपने घर की मरम्मत उधार लेकर करनी पड़ती है। लोगों का कहना है कि अगर समय पर उचित सहायता मिले तो वे नुकसान से जल्दी उबर सकते हैं और दोबारा सामान्य जीवन शुरू कर सकते हैं।

### मैपिया भुगतान भी बना बड़ी परेशानी

ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग से मिलने वाली मैपिया राशि का भुगतान भी समय पर नहीं हो पाता है। कई प्रभावित परिवार महीनों तक कार्यालयों के चक्कर लगाते रहते हैं। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। उनका कहना है कि नुकसान का सही आकलन कर तय समय सीमा के भीतर छत्तीसगढ़ सरकार के जैसे ही समान भुगतान होना चाहिए। राहत तभी मायने रखती है जब वह समय पर समान रूप से जरूरतमंद तक पहुंचे।

### सत्यनारायण राठौर ने उठाई बराबरी की मांग

युवा नेता सत्यनारायण राठौर ने सरकार से मांग

की है कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी मकान क्षति पर 1.20 लाख से 1.30 लाख रुपये तक मुआवजा दिया जाए। उनका कहना है कि सीमा के इस पार रहने वाले ग्रामीण किसी भी तरह कम पीड़ित नहीं हैं। उन्होंने शासन प्रशासन से हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लिए अलग राहत योजना बनाने और मैपिया राशि का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने की भी मांग की है।

### अब फैसला सरकार के हाथ में

हाथियों का आतंक केवल वन विभाग का विषय नहीं, बल्कि ग्रामीणों के जीवन, खेती और भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। शासन और प्रशासन यदि समय रहते बेहतर मुआवजा नीति और तेज राहत व्यवस्था लागू करती है तो प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत मिल सकती है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि भोपाल तक पहुंची यह आवाज जमीन पर भी काम करेगी ? दूसरी ओर प्रभावित जनता अपने जनप्रतिनिधियों को ओर टकटकी लगाए बैठी है कि प्रभावित गांवों को वास्तव में न्याय और बराबरी का अधिकार मिलता है या नहीं.....!

## करंट लगने और ट्रेन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत, पुलिस जांच में जुटी

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।

जिले में गुरुवार को हुई दो अलग-अलग दर्दनाक घटनाओं में दो युवकों की मौत हो गई। पहली घटना में पुराने कुएं से मोटर पंप निकालते समय करंट लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी घटना में हरद रेलवे स्टेशन के समीप अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की जान चली गई। दोनों मामलों में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम सेंदुरी में रहने वाले हीरालाल बैगा (27) पिता लालमन बैगा गुरुवार शाम अपने घर के पीछे स्थित बाड़ी में पुराने कुएं से मोटर पंप निकाल रहे थे। परिजनों के अनुसार मोटर पंप को चोरी से बचाने के उद्देश्य से उसे निकालने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान अचानक करंट की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पत्नी कविता बैगा ने बताया कि घटना के समय हीरालाल अकेले पंप निकाल रहे थे। कुछ देर बाद उनकी बहन बाड़ी की ओर गई तो उन्होंने हीरालाल को जमीन पर पड़े और हाथ में बिजली का तार पकड़े देखा।

शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें तत्काल जिला अस्पताल अनूपपुर ले जाया गया, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस सहायता केंद्र जिला अस्पताल एवं कोतवाली पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम कराया तथा मामले की जांच शुरू कर दी है। दूसरी घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के खांड़ा गांव निवासी विजय सिंह (35) पिता लालजी सिंह के साथ हुई। बताया गया कि विजय सिंह गुरुवार को अपने रिश्तेदारों से मिलने भालूमाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम छोहरी-परासी गए थे। रात में वापस लौटते समय हरद रेलवे स्टेशन के समीप अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना हरद स्टेशन मास्टर द्वारा दिए जाने पर जीआरपी चौकी अनूपपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान कराई। परिजनों की मौजूदगी में पंचनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस दोनों घटनाओं के कारणों की विस्तृत जांच कर रही है।

# करैत सर्प के डंसने से 6 वर्षीय बालिका की मौत

## 48 घंटे में सर्प प्रहरियों ने 20 से अधिक सांपों का किया रेस्क्यू, जंगल में छोड़ा

**हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।** जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच जहरीले सांपो का रिहायशी क्षेत्रों में निकलना लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। भालूमाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बाड़ीखार के भेड़वाटोला में करैत सर्प के डंसने से एक 6 वर्षीय बालिका की मौत हो गई, जबकि उसके माता-पिता जिला चिकित्सालय में उपचाररत हैं। वहीं, अनूपपुर नगर में जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ में पदस्थ उपयंत्री इंद्रजीत पटेल भी करैत सर्प के हमले से बाल-बाल बच गए। इधर, जिले के सर्प प्रहरियों ने पिछले 48 घंटों में 20 से अधिक सांपो का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत बाड़ीखार के भेड़वाटोला निवासी भानु प्रताप सिंह गुरुवार रात अपनी पत्नी रेखा सिंह और 6 वर्षीय पुत्री माधवी के साथ घर के अंदर तख्त पर सो रहे थे। देर रात करीब 2 बजे एक अत्यंत विषैला करैत सर्प घर के भीतर पहुंच गया और सो रहे तीनों को डंस लिया। परिजन तत्काल उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय अनूपपुर रेफर किया गया। चिकित्सकों ने जांच के दौरान 6 वर्षीय माधवी को

मृत घोषित कर दिया, जबकि भानु प्रताप सिंह और रेखा सिंह का उपचार जारी है। घटना की जानकारी मिलने पर सर्प प्रहरी शशिधर अग्रवाल जिला चिकित्सालय पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। प्रारंभिक आशंका है कि करैत सर्प अभी भी घर के भीतर अलमारी के आसपास छिपा हो सकता है। घर बंद होने के कारण तत्काल खोजबीन नहीं हो सकी। कोतमा के सर्प प्रहरी हरिवंश प्रसाद पटेल घर खुलने का इंतजार कर रहे हैं ताकि सर्प का सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके। इसी बीच, अनूपपुर नगर के वार्ड क्रमांक 10 स्थित बब्बा कॉलोनी निवासी एवं जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ में पदस्थ उपयंत्री इंद्रजीत पटेल भी एक बड़ी दुर्घटना से बच गए। देर रात घर से बाहर निकलते समय दरवाजे के पास बैठे करैत सर्प पर उनका पैर पड़ते-पड़ते बचा। सूचना मिलने पर सर्प प्रहरी शशिधर अग्रवाल मौके पर पहुंचे और लगभग दो फीट लंबे करैत सर्प का सुरक्षित रेस्क्यू किया। सर्प प्रहरी शशिधर अग्रवाल, छोटेलाल यादव, मनोज यादव, धर्मेंद्र यादव, लालदास सिंह और देवराज कोल ने पिछले 48 घंटों में अनूपपुर नगर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से 20 से अधिक सर्पों का रेस्क्यू किया। इनमें कोबरा, करैत, अजगर, धामन सहित अन्य प्रजातियों के सर्प शामिल हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी स्वर्ण गौरव सिंह की उपस्थिति में इन सभी सर्पों को किरर बीट के डोकरीआरा स्थित घने जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। सर्प प्रहरियों ने लोगों से अपील की है कि बारिश के मौसम में घरों के आसपास साफ-सफाई रखें, रात के समय सावधानी बरतें तथा किसी भी प्रकार का सर्प दिखाई देने पर उसे पकड़ने का प्रयास न करें, बल्कि तत्काल प्रशिक्षित सर्प प्रहरियों या वन विभाग को सूचना दें।

**हाईकोर्ट से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत**

# सरकार की अपील खारिज, एरियर भुगतान का आदेश बरकरार, वर्षों से लंबित मांग पूरी होने की उम्मीद

**हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।** मध्यप्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जबलपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए एकलपीठ के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को बकाया एरियर का भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे।

न्यायालय के इस फैसले से प्रदेशभर की हजारों कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को आर्थिक लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मामला वर्ष 2019 में मानदेय भुगतान की व्यवस्था में हुए बदलाव से जुड़ा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का आरोप था कि पूर्व में मिलने वाले मानदेय में कटौती किए जाने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इस निर्णय को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। एकलपीठ ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि कटौती की गई राशि का एरियर पात्र कार्यकर्ताओं को दिया जाए। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी, लेकिन न्यायालय ने सरकार की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और एरियर भुगतान संबंधी आदेश को यथावत रखा। हालांकि, सरकार को ब्याज भुगतान के मामले में आंशिक राहत मिली है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेशभर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं में खुशी का माहौल है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि लंबे समय से लंबित इस मामले में न्याय मिलने से हजारों परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। साथ ही यह निर्णय भविष्य में कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़े मामलों में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एटक मध्यप्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष विभा पांडे ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह प्रदेश की लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लंबे संघर्ष की ऐतिहासिक जीत है। उन्होंने कहा कि सरकार को न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए बिना किसी देरी के सभी पात्र कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के खातों में एरियर राशि का भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह फैसला केवल आर्थिक राहत नहीं, बल्कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्मान, अधिकार और न्याय की भी जीत है। प्रदेशभर के आंगनबाड़ी कर्मचारी संगठनों ने भी फैसले का स्वागत करते हुए सरकार से मांग की है कि न्यायालय के आदेश का शीघ्र पालन किया जाए, ताकि वर्षों से लंबित बकाया राशि का भुगतान समयबद्ध तरीके से किया जा सके और कर्मचारियों को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े। हाईकोर्ट के इस निर्णय को प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी उपलब्धि माना जा रहा है।

# कलेक्टर ने स्वच्छता व्यवस्था का किया औचक निरीक्षण

## ट्रेंचिंग ग्राउंड और कचरा प्रबंधन सुधारने के दिए सख्त निर्देश

**हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।** जिले में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर हर्षल पंचोली ने शुक्रवार को नगर पालिका अनूपपुर क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नई सब्जी मंडी के पीछे स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड तथा जैतहरी रोड स्थित पुराने ट्रेंचिंग ग्राउंड का जायजा लेते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पुराने ट्रेंचिंग ग्राउंड की उपलब्धता के बावजूद नए स्थान पर कचरा डंप करना उचित नहीं है। उन्होंने नवीन ट्रेंचिंग ग्राउंड में जमा कचरे को पुराने ट्रेंचिंग ग्राउंड में स्थानांतरित कर वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित तरीके से उसके निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने नगर पालिका अधिकारियों के साथ स्वच्छता व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नगर के प्रत्येक वार्ड में नियमित और समयबद्ध सफाई सुनिश्चित करने के लिए सफाई कर्मचारियों की शिफ्टवार ड्यूटी तय की जाए तथा उनकी दैनिक निगरानी की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर की स्वच्छता में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने नगर पालिका के कचरा संग्रहण वाहनों की जानकारी भी ली। अधिकारियों ने बताया कि नगर पालिका के पास छह कचरा संग्रहण वाहन उपलब्ध हैं, जो प्रतिदिन सभी वार्डों में घर-घर पहुंचकर कचरा एकत्रित करते हैं। इस पर उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक घर से नियमित रूप से कचरा संग्रहित किया जाए और किसी भी वार्ड में कचरा संग्रहण कार्य बाधित नहीं होना चाहिए।

उन्होंने गीले, सूखे एवं अन्य प्रकार के अपशिष्ट का पृथक-पृथक संग्रहण सुनिश्चित करने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि स्रोत स्तर पर कचरे का पृथक्करण प्रभावी स्वच्छता प्रबंधन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। नगर पालिका के कर्मचारी इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराएं तथा नागरिकों को भी इसके प्रति जागरूक करें, ताकि शहर को स्वच्छ और प्रदूषणमुक्त बनाया जा सके। कलेक्टर हर्षल पंचोली ने निरीक्षण के दौरान स्मार्ट सिटी क्षेत्र एवं पुलिस लाइन के विभिन्न आवासों में स्वयं पहुंचकर घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय नागरिकों से बातचीत कर स्वच्छता व्यवस्था की वास्तविक स्थिति और नगर पालिका की कार्यप्रणाली के संबंध में फीडबैक भी लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाए और सफाई व्यवस्था में निरंतर सुधार लाया जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सफाई कर्मचारियों एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्य में किसी प्रकार की उदासीनता या लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक कर्मचारी अपने दायित्वों का पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन करे, ताकि नगर की स्वच्छता व्यवस्था लगातार बेहतर बनी रहे। कलेक्टर ने कहा कि स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ शहर का निर्माण केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि नागरिकों की भी साझा जिम्मेदारी है। प्रभावी कचरा प्रबंधन, नियमित सफाई और जनसहभागिता से ही स्वच्छता अभियान को सफल बनाया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी शशांक आर्मो, उपयंत्री एवं नगर पालिका के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

# हादसों के बाद भी नहीं सुधरी व्यवस्था, हाईवे पर अवैध पार्किंग के खिलाफ अनिल गुप्ता ने खोला मोर्चा

## कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन, कहा अवैध पार्किंग नहीं रुकी तो फिर हो सकते हैं बड़े हादसे

**हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।** जिले के राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर भारी वाहनों की अवैध पार्किंग लगातार सड़क हादसों का कारण बन रही है। कई दर्दनाक दुर्घटनाओं के बावजूद व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर पूर्व विंध्य विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार गुप्ता ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक अनूपपुर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने अवैध रूप से सड़क किनारे खड़े किए जा रहे भारी वाहनों के विरुद्ध तत्काल और नियमित कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में होने वाली गंभीर दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की होगी। ज्ञापन में श्री गुप्ता ने कहा है कि जैतहरी-अनूपपुर, चचाई-अनूपपुर तथा कोतमा-अनूपपुर जैसे प्रमुख मार्गों पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में ट्रक एवं अन्य भारी मालवाहक वाहन सड़क किनारे घंटों और कई बार पूरी रात खड़े रहते हैं। इससे यातायात बाधित होने के साथ-साथ विशेषकर रात्रि के समय दुर्घटनाओं की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि जिन राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों का निर्माण सुरक्षित और सुगम आवागमन के लिए किया गया था, वे अब धीरे-धीरे अवैध पार्किंग स्थल में तब्दील होते जा रहे हैं।

उन्होंने विशेष रूप से आरोप लगाया कि जैतहरी स्थित एम.बी. पावर प्लांट से फ्लाई ऐश (राखड़) परिवहन में लगे सैकड़ों भारी वाहन दुर्गादास चौक से लेकर अनूपपुर के तिपान नदी क्षेत्र तक सड़क किनारे लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। इससे आम लोगों, दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। श्री गुप्ता ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर हुए उस दर्दनाक हादसे का उल्लेख भी किया, जिसमें पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के एक ही परिवार के 5 लोगों की सड़क किनारे खड़े भारी वाहन से टकराने के कारण मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि यह दुर्घटना केवल एक घटना नहीं बल्कि प्रशासन के लिए गंभीर चेतावनी है। यदि इसके बाद भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती है तो भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा हो सकते हैं।

उन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी बड़ी दुर्घटना के बाद कुछ दिनों तक विशेष अभियान चलाकर खानापूर्ति कर ली जाती है, लेकिन अभियान समाप्त होते ही फिर वही स्थिति बन जाती है। सड़क सुरक्षा केवल औपचारिक अभियान चलाने से सुनिश्चित नहीं होगी, बल्कि नियमित निगरानी, सतत जांच और कानून के सख्त पालन से ही आम नागरिकों की जान बचाई जा सकती है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर अवैध रूप से पार्क किए जाने वाले भारी वाहनों के खिलाफ नियमित विशेष अभियान चलाया जाए, दोषी वाहन मालिकों एवं चालकों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए तथा भविष्य में ऐसी अव्यवस्था रोकने के लिए स्थायी और प्रभावी व्यवस्था लागू की जाए। अनिल कुमार गुप्ता ने इस ज्ञापन की प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय भोपाल एवं पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन को भी प्रेषित करते हुए शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि सड़क सुरक्षा किसी राजनीतिक दल का विषय नहीं बल्कि जनहित और जनजीवन की सुरक्षा से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऐसे में प्रशासन को संवेदनशीलता दिखाते हुए बिना किसी विलंब के प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

## अमरकंटक के समग्र विकास पर संत समाज और प्रशासन का मंथन

**हरिभूमि न्यूज अमरकंटक।** विश्व प्रसिद्ध तीर्थनगरी अमरकंटक के समग्र विकास, धार्मिक परंपराओं के संरक्षण तथा श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को सर्किट हाउस सभागार में मध्यप्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला विकास प्राधिकरण, भोपाल तथा जिला प्रशासन अनूपपुर के संयुक्त तत्वावधान में संत समाज, पुजारियों, आश्रम प्रबंधकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मध्यप्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) डॉ. राजेन्द्र श्रीवास्तव ने की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. श्रीवास्तव ने कहा कि अमरकंटक केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र है।

**कार्यालय नगर परिषद बनगवाँ, (राजनगर) जिला-अनूपपुर (म.प्र.)**
Office: Municipal Council Bangavan Dist- Anuppur (M.P.) Email-cmobangavan@mpurban.gov.in
क्रमांक-1458/न.प./लो.नि./ई-निविदा/2026 // निविदा सूचना // बनगवां, दिनांक 10/07/26
निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

| क्र. | टेण्डर क्रं. जारी दिनांक | कार्य का नाम | कार्य की समयावधि एवं लागत | निविदा का मूल्य एवं EMD | निविदा की अंतिम तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026_UAD_520298_1 | Construction of Sewage Treatment Plant (STP) At Bangawan Park, Dist Anuppur (M.P) Under SBM 2.0 Scheme • Design and build 1 Nos. sewage treatment plant of installed capacity 0.8 MLD of Constructed Wetland based, and all appurtenant structures and allied works; • Survey, review the designs, redesign where necessary, and diversion works of Nallahs with Interception sewer of about 2.8 Km length which includes Pumping • Main Comprising of DI-K7 class pipe of 100 mm to 150 mm diameter having length of 2700m & Gravity Main Comprising of RCC NP3 Pipe of 500 mm diameter having length of 100m, • Construction of 2 nos. I&D Structure at Nallah • Construction of 2 Nos of Screen Chamber • Construction of 01 no. Intermediate Pumping station 0.6 MLD. • Construction of 01 no. Main Pumping station 0.8 MLD. • Strengthening of drain having length 450 m Including survey, design and all appurtenant structures and allied works Providing and Layingof 1 Km of HT Line, | 12 months Including rainy season Rs 497.44 lakh | Rs 15000.00 Rs. 248720.00 | 10.08.2026 |

नोट :- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाइट पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नही किया जायेगा।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद बनगवाँ राजनगर जिला - अनुपपुर (म.प्र.)